

प्रेषक,

सुनील श्री पांथरी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,  
मानव अधिकार आयोग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 10 अप्रैल, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29-03-2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की मांगे स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी "विनियोग अधिनियम, 2019" पारित होने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक 2055-पुलिस-001-निदेशन और प्रशासन-09-राज्य मानवाधिकार आयोग के मानक मद संख्या 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 3,00,00,000/- (रू0 तीन करोड़ मात्र) वित्त विभाग के उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 29-03-2019 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक 2055-पुलिस-001-निदेशन और प्रशासन-09-राज्य मानवाधिकार आयोग के मानक मद संख्या 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायतके नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधायित अधिकारों के क्रम में एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

5- उक्त प्रस्तर-4 पर संदर्भित वित्त अनुभाग-01 के शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील श्री पांथरी)  
अपर सचिव

संख्या- 58 /XX-4 / 2019-4(38) / 2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग-5
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)  
उप सचिव